शामिल है, सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ग) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष के दौरान वित्त और विविध आय सहित प्रचालन आय

	पत्तन न्यास का नाम	1992-93	1993-94	1994-95 (करोड़ रू.)
1	बम्बई पत्तन न्यास	437.22	484.82	558.51
2.	कलकत्ता पत्तन न्यास	335.46	413.20	468.62
3.	कोचीन पत्तन न्यास	80.56	80.69	94.61*
4.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	103.50	124.28	179.07
5.	कांडला पत्तन न्यास	119.48	139.96	157.97
6.	मद्रास पत्तन न्यास	256.64	300.29	310.08
7.	मुरगांव पत्तन न्यास	79.12	98.96	97.41
8.	न्यू मंगलौर पत्तन न्यास	41.97	48.31	48.21
9.	पारादीप पत्तन न्यास	103.03	132.73	138.37*
10.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	39.88	39.09	45.02
11.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	189.56	202.26	219.41
		1786.42	2064.59	2137.28

*आंकड़े अन्तिम हैं।

गुजरात द्वारा कच्छ क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाने की मांग

946. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कच्छ क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड बनाने और इस प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस लंबित मांग को स्वीकृत प्रदान करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है,

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है, और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन): (क) से (ड.) गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र के विकास बोर्डो की भांति ही "कच्छ विकास बोर्ड" की स्थापना के लिए अनुमोदन चाहा है। हालांकि, राज्य सरकार ने इस अनुरोध पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि मामले की विभिन्न कानूनी, संवैधानिक एंव राजनैतिक जटिलताओं को देखते हुए, इस मामले में निर्णय लिए जाने के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

Food processing units in economically and industrially backward areas of Madhya Pradesh

947. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal for setting up food processing units in economically and industrially backward areas of the State